



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 10, 2017 (ASADHA 18, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 10 जुलाई, 2017

संख्या डी०पी०एच०-एल०ए०-2017/802.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में सभी ग्राम पंचायतों से ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत के लिए विद्युत बिल के दो प्रतिशत की दर से विद्युत के उपभोग पर पंचायत कर उद्ग्रहण करने के लिए अपेक्षा करते हैं। यह कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संगृहीत किया जायेगा और उसी रीति में भुगतान किया जायेगा मानो यह हरियाणा राज्य को भुगतान योग्य विद्युत शुल्क था और वह संबंधित ग्राम पंचायत को लौटाया जायेगा। कर भारत सरकार द्वारा विद्युत के उपभोग पर या जहां यह भारत सरकार द्वारा किसी रेल के निर्माण, रख-रखाव या परिचालन में उपभोग की जाती है, उद्ग्रहणीय नहीं होगा। यह कर इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा उद्ग्रहणीय होगा।

नवराज संधु ,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT*****Order***

The 10th July, 2017

No. DPH-LA-2017/802.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) of Section 41 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby requires all Gram Panchayats within the State of Haryana to levy Panchayat Tax on the consumption of electricity at the rate of two per centum of the electricity bill for the electricity consumed by any consumer within the limits of the Gram Panchayat. This tax shall be collected by the Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited (UHBVN & DHBVN) and paid in the same manner, as if it was electricity duty payable to Government of Haryana and the same shall be remitted to the concerned Gram Panchayat. The tax shall not be leviable on consumption of electricity by Government of India or where it is consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India. This tax shall be leviable by each Gram Panchayat within a period of 15 days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.